



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. // NREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2011 / 6612

भोपाल, दिनांक 22/06/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
जिला पंचायत ..... (समस्त)

विषय:- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत रोजगार मूलक कार्यों हेतु वित्त वर्ष 2011-12 में अतिरिक्त किशत के प्रस्ताव विषयक।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के संचालन हेतु परिषद् स्तर "राज्य रोजगार गारंटी निधि" के द्वारा समानुपातिक केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जिलों को जारी की जा रही हैं। इस वित्त वर्ष 2011-12 में राशि प्राप्त करने हेतु यह उल्लेखनीय है कि गतवर्ष के अंतिम शेष के आंकड़ों एवं इस वित्त वर्ष में प्राप्त धनराशि इस प्रकार से कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध 60 प्रतिशत व्यय एवं उसका MIS होने पर ही जिलों द्वारा राशि की मांग की जा सकेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि 60 प्रतिशत व्यय एवं MIS का लक्ष्य जिलों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा अतः जिले के अंदर विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों में आंतरिक धन प्रवाह के समुचित प्रबंधन का उत्तरदायित्व जिले का होगा। राशि किसी भी स्तर पर अवरुद्ध न हो साथ ही स्कीम का संचालन भी बाधित न हो। इस स्थिति को भी निरंतर समीक्षित करना होगा।

अतः उपलब्ध राशि के विरुद्ध 60 प्रतिशत व्यय एवं उसके MIS होने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए राशि मांग के प्रस्ताव भेजे जायें। निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

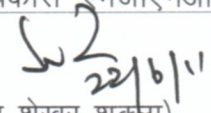
1. निर्धारित प्रारूप B-16 में राशि की मांग।
2. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र B-17 (गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष) की अद्यतन स्थिति एवं वर्तमान में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध 60 प्रतिशत व्यय होने की अनिवार्यता।
3. अद्यतन एमआईएस रिपोर्ट एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन।
4. लेबर बजट की प्रति।
5. कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति।
6. शिकायतों के निराकरण की वस्तुस्थिति तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अद्यतन स्थिति।
7. संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार प्रमाण पत्र।

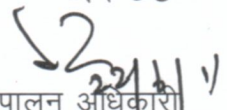
उपरोक्त दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेज के संलग्न न होने पर प्रस्ताव संबंधित जिले को मूलतः वापिस कर दिया जावेगा। राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी एमजीएनआरईजीएस के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संलग्न: यथोपरि

पृ क्र. // NREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2011 / 6613  
प्रतिलिपि:

समस्त संभागायुक्त म. प्र. की ओर सूचनार्थ।

  
(शिव शेखर शुक्ला)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल, दिनांक 22/06/11

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. अंतिम शेष चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष के आंकड़े समान है और निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शित प्रारंभिक और अंतिम शेष के आंकड़े तदानुसार हैं। साथ ही अंतिम शेष के आंकड़े ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही प्राप्त किये गये हैं।
2. प्राप्त की गई सभी निधियां केवल अधिकृत बचत बैंक खाते में ही जमा की गई हैं।
3. समानुपातिक केन्दांश एवं राज्यांश उपलब्ध हैं।
4. लेखांकन शुद्ध होकर लेखों की अंक गणितीय गणना शुद्ध है।
5. शासकीय धन जिले में संचालित खातों में कहीं पर भी अवस्द्ध नहीं है एवं धन की वास्तव में आवश्यकता है।
6. उपलब्ध धन राशि के विरुद्ध 60 प्रतिशत व्यय हो चुका है।
7. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित संकर्मों की लागत के अनुसार निधियों का कम से कम पचास प्रतिशत अनुबंधित अवधि के भीतर ग्राम पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है।
8. राशि नियमानुसार अधिनियम के प्रावधानों के पालन अनुसार एवं प्रक्रिया अनुसार उपयोग की गई हैं तथा श्रम एवं सामग्री (60:40) का पालन किया जा रहा है। विधिवत अभिलेखों का भी संधारण किया जा रहा है।
9. राशि के व्यपवर्तन (Diversion) एवं गबन (व्यपहरण- Embezzlement)संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।
10. राशि का सावधि जमा नहीं किया गया।
11. राशि पर बैंक द्वारा प्रचलित दरों पर ब्याज दिया गया है व संस्था द्वारा इसे स्कीम में सम्मिलित किया गया है।
12. सामग्री क्रय में समुचित वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जा रहा है।
13. लेखों का बंदीकरण एवं बैंक समाशोधन मासिक रूप से किया जा रहा है।
14. अग्रिमो को व्यय के रूप में नहीं दर्शाया गया है।
15. दस प्रतिशत एवं सौ प्रतिशत कार्यों का भौतिक एवं मस्टर रोल के सत्यापन नियमानुसार किया जा रहा है।
16. मस्टर रोल स्कीम की दिशा निर्देशानुसार संधारित किए हैं।
17. सामाजिक लेखा परीक्षण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
18. जॉब कार्ड धारी अकुशल श्रमिकों को अकुशल श्रम भुगतान शत-प्रतिशत बैंक/पोस्ट ऑफिस से किया जा रहा है।
19. कार्यों का नियमित मूल्यांकन किया जा रहा है।
20. प्रशासनिक व्यय की सीमा एवं निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम  
समन्वयक

लेखाधिकारी  
(एमजीएनआरईजीएस)

जिला कार्यक्रम  
समन्वयक